भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2141
14 मार्च, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पीएलआई योजना

2141. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी कोई प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है और यदि हां, तो इस योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) इस योजना से पूर्वोत्तर राज्यों को किस प्रकार लाभ होगा;

(ग) इस हेतु अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा चयनित आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार के पास न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किया जाएगा ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): जी हाँ।, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.03.2021 को अपनी बैठक में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत की प्राकृतिक संसाधन प्रदत्त निधि और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता के अनुरूप वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन के निर्माण में सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पी एल आई एस एफ पी आई)" का अनुमोदन किया है । योजना के कार्यान्वयन से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की क्षमता का विस्तार करने और रोजगार सृजित करने में सुविधा होगी।

योजना का पहला घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों यानि रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ जिसमें मिलेट आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़ेरेला चीज़ शामिल हैं, से संबन्धित है। दूसरा घटक , इन चार खंडों में लघु और मध्यम उद्यमों जिसमें फ्री रेंज –अंडे, पौल्ट्री मांस, अंडा उत्पाद के नवीन/जैव उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। । तीसरा घटक मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए समर्थन से संबंधित है । बचत से, 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2022-23 में बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक और घटक जोड़ा गया है।

(ख) और (ग): यह योजना किसी राज्य या क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से एक आवेदन मैसर्स सना इंटरप्राइजेज का मिलेट आधारित उत्पादों के लिए प्राप्त हुआ और उसका चयन किया गया। परंतु पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत इस प्रकार शामिल हैं :

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**ज़िला**	**राज्य**
1	सना इंटरप्राइजेज	दीमापुर	नागालैंड
2	बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड	कामरूप	असम
3	प्रताप स्नैक्स लिमिटेड	कामरूप (2 इकाइयां)	असम

(घ): सरकार ने दिसंबर, 2021 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में न्यूट्रास्यूटिकल क्षेत्र पर एक कार्यबल का गठन किया, ताकि न्यूट्रास्यूटिकल क्षेत्र पर बल देने के लिए एक रोड मैप विकसित किया जा सके और इसके द्वारा क्षेत्र की विकास क्षमता का उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके प्रकट करने की सुविधा प्रदान की जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस टास्क फोर्स का सदस्य है।

*****